THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT(SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Yes Sir.

(b) A representation of the Government of India Press, Photo Litho Trade Workers Union, Minto Road was forwarded by Sh. Nawal Kishore Sharma, Member of Parliament (Lok Sabha) on 24.10.97 for up-gradation of the pay-scale of PTS Key Board Operators of Government of India Presses from the pre-revised scale of Rs. 1400-2300 to the revised scale of Rs. 5000-8000.

The PTS Key Boad Operators of the Government of India Presses have been accorded the revised pay scale of Rs. 4500-7000/- which is the normal replacement scale for the pre-revised pay scale of Rs. 1400-2300/-

The request for up-gradation of the pay scale of PTS Key Board Operators in the Government of India Presses was not agreed to.

(c) Does not arise.

Committee of Technical Experts

2156. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to refer to the answer given in the Rajya Sabha on 21st December, 1998 in reply to Unstarred Question No. 2462 and state:

(a) the detailed terms of reference of the Committee of Technical Experts set up under the Chairmanship of Commissioner (Planning);

(b) whether this Committee has submitted its report/recommendation;

(c) if so, the details of action taken thereon; and

(d) if the answer to part (b) in negative, by when the Committee is scheduled to give its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATATREYA): (a) The Committee of Technical Experts under the Chairmanship of Commissioner (Planning), DDA, was set up to suggest the feasibility of more covered area in DDA flats.

(b) The Committee has not yet submitted the final report/recommendations.

(c) and (d) The Committee met twice on 32.10.98 and 6.1.99. The report/recommendations are under process of finalisation.

शहरी क्षेत्रों में बेघर लोग

2157. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों की संख्या का पता करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम विद्यमान है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूर तथा कलकत्ता जैसे महानगरों में रियायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने हेतु गंभीर प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का उद्देश्य शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के भाग से रूप में प्रति वर्ष 2 मिलियन मकान उपलब्ध कराना है। इनमें से 7 लाख मकान शहरी क्षेत्र में होंगे हाल ही में की गई प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि 7 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तथापि यह राज्य सरकारों के प्रत्युत्तर पर भी निर्भर है कि वे अपनी परियोजनाएं हडको को समय पर प्रस्तुत करें।

(घ) और (ङ) सस्ते मकान उपलब्ध कराने के सरकारी नीति के भाग के रूप में हडको द्वारा दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर तथा कलकत्ता के चार महानगरों सहित सारे देश में विभिन्न क्षेणियों विशेषकर ई डब्ल्यू एस तथा